

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2891

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

गांवों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाना

2891. डा. सत्यनारायण जटिया:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार कुल गांवों की संख्या में से स्वच्छ पेयजल से वंचित गांवों की संख्या कितनी है तथा आगामी पांच वर्षों में गांवों को वर्ष-वार स्वच्छ पेयजल प्रदान करने की कार्य योजना क्या है तथा सभी गांवों को शुद्ध पेयजल प्रदान करने का क्या लक्ष्य तय किया गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

यह मंत्रालय बसावटों के संबंध में कवरेज की सूचना का रखरखाव करता है न कि गांवों के संबंध में। जिन बसावटों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है उनकी राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

इस मंत्रालय ने 2011-2022 की अवधि के लिए ग्रामीण पेयजल सेक्टर के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक घरों को नल जल आपूर्ति देने पर बल दिया गया है। वर्ष 2017 तक अंतरिम लक्ष्य है सभी ग्रामीण परिवारों के 50% को नल जल आपूर्ति द्वारा कवर करना। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को नलजल आपूर्ति द्वारा कवर करने का लक्ष्य है।

दिनांक 12.12.2016 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2891 में उल्लिखित
अनुलग्नक

उन ग्रामीण बसावटों का ब्यौरा जिन्हें दिनांक 07.12.2016 की स्थिति के अनुसार सुरक्षित पेयजल
प्राप्त नहीं हो रहा है

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या (रासायनिक संदूषण से प्रभावित)
1	अंडमान और निकोबार	400	0
2	आंध्र प्रदेश	48342	526
3	अरुणाचल प्रदेश	7577	55
4	असम	88099	8782
5	बिहार	110234	5260
6	छत्तीसगढ़	74647	1123
7	गोवा	347	0
8	गुजरात	36066	0
9	हरियाणा	7948	206
10	हिमाचल प्रदेश	53604	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	15958	5
12	झारखंड	120067	6605
13	कर्नाटक	60220	1906
14	केरल	11883	656
15	मध्य प्रदेश	128067	153
16	महाराष्ट्र	100066	392
17	मणिपुर	2868	0
18	मेघालय	10475	10
19	मिजोरम	738	0
20	नागालैंड	1530	43
21	ओडिशा	156468	2667
22	पुडुचेरी	266	0
23	पंजाब	15384	3709
24	राजस्थान	121648	20633
25	सिक्किम	2084	0
26	तमिलनाडु	100204	351
27	तेलंगाना	24582	1481
28	त्रिपुरा	8723	3962
29	उत्तर प्रदेश	260801	361
30	उत्तराखंड	39209	18
31	पश्चिमी बंगाल	105905	9790
कुल		1714528	68694
प्रतिशत			4.01

(स्रोत: मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का सी-17 फॉर्मेट)